"ईरान की परमाणु समस्या"

IAEA ने कहा कि ईरान परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। अतः वह NPT का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि NPT में केवल शान्तिपूर्ण प्रयोग की अनुमति है

→ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने U.N. ~~पर~~ के द्वारा आर्थिक व व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाये हैं

समस्या सुधार समाधान के लिए पहल –

सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों एवं जर्मनी ने मिलकर ईरान से परमाणु संवर्द्धन कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की

जबकि ईरान का दावा है कि परमाणु संवर्द्धन का अधिकार NPT सन्धि से प्राप्त हुआ है क्योंकि इस सन्धि में परमाणु क्षमता के शान्तिपूर्ण प्रयोग का अधिकार है।

ईरान के नये राष्ट्रपति रोहानी ने अमेरिका के साथ बातचीत की पहल की है परंतु उन्होंने कहा कि ईरान पर लागू सभी प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त होने चाहिए तभी कोई सार्थक बातचीत संभव है।

रोहानी के समक्ष विद्यमान नयी चुनौतियां –

ईरान के नये राष्ट्रपति रोहानी उदारवादी माने जाते हैं

वे खाड़ी सहयोग परिषद से संबंध बेहतर करना चाहते हैं

→ सऊदी अरब के साथ बेहतर संबंधों का निर्माण
→ ईरान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना
→ सीरिया को समर्थन बनाये रखना

ईरान के बारे में भारत का दृष्टिकोण -

→ भारत ईरान के शान्तिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थक है

→ परंतु भारत, ईरान के परमाणु हथियारों के निर्माण का समर्थक नहीं है

→ भारत के अनुसार समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए

CTBT

Comprehensive Test Ban Treaty

ये Comprehensive इसलिए है कि इसमें सभी प्रकार के परीक्षण सम्भव नहीं है। N5 सहित कोई भी राज्य परमाणु परीक्षण नहीं करेगा

यह संधि तभी लागू होगी जब परमाणु अनुसंधान की सुविधा से युक्त सभी 44 देश इस हस्ताक्षर करेंगे इसे entry into force clause के नाम से भी जाना गया।

इसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण केन्द्र व अन्तर्राष्ट्रीय डाटा केन्द्र का निर्माण किया गया।

यह लागू नहीं हो सका क्योंकि

भारत पाकिस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किये
अमेरिका चीन देशों के हस्ताक्षर के बाद भी विधायिका ने पारित नहीं किया

भारत ने NPT का विरोध N5 व अन्य मे विभेद के कारण ~~और केवल अप्रसार की बात करने के कारण~~

CTBT का विरोध केवल अप्रसार पर नियंत्रण के कारण किया क्योंकि यह निःशस्त्रीकरण की बात नहीं करता

CTBT तकनीकी रूप से व्यर्थ है क्योंकि यह विस्फोट कंप्यूटर पर भी संभव है

साथ ही विरोध का अन्य कारण इन संधियों द्वारा ~~पर~~ तकनीक हस्तान्तरण पर रोक के कारण है।

भारत का परमाणु परीक्षण

उद्देश्य

विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास

नीति

भारत ने सभी परमाणु परीक्षण पर एकतरफा प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की

- → भारत कभी भी परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा
- → गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश पर कभी भी परमाणु हथियारों का हमला नहीं करेगा
- → भारत के परमाणु हथियारों पर PM का नियन्त्रण होगा सेना का नहीं

(5) भारत अपने परमाणु अनुसंधान व विकास का कार्यक्रम जारी रखेगा

(6) भारत के द्वारा परमाणु दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगा।

(7) अभी भी भारत समूचे विश्व से परमाणु हथियारों की समाप्ति का समर्थक

पहले प्रयोग की नीति —

के विपक्ष में तर्क — चीन के द्वारा 2013 में घोषित सुरक्षा श्वेत पत्र में पहली बार पहले प्रयोग न करने की नीति का उल्लेख नहीं किया गया है

(8) पाकिस्तान का दृष्टिकोण भारत के प्रति अत्यधिक आक्रामक है और पाकिस्तान पहले प्रयोग न करने की नीति को स्वीकार नहीं करता

→ आलोचकों के अनुसार एक राज्य के परमाणु हमले के बाद दूसरे को आक्रमण करने का समय ही नहीं मिलेगा इसलिए यह नीति निरर्थक है

→ अमेरिका रूस जैसी महाशक्ति भी पहले ~~न~~ प्रयोग की नीति को स्वीकार करते हैं।

पक्ष में तर्क –

पहले प्रयोग न करने की नीति भारत की परमाणु नीति के अनुकूल है क्योंकि भारत के परमाणु परीक्षण का उद्देश्य आक्रामक नहीं बल्कि सुरक्षात्मक है।

→ चीन के द्वारा अभी भी आधिकारिक रूप में पहले प्रयोग न करने की नीति का परित्याग नहीं किया गया है।

→ भारत एक उत्तरदायी राज्य है जिसकी तुलना पाकिस्तान से करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

पहले न प्रयोग करने की नीति सैद्धान्तिक है युद्ध जैसी आपवादिक परिस्थितियों में इन सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जाता। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में शान्तिपूर्ण नीति बेहतर विकल्प है

भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौता२०..

(a) यह ऊर्जा के लिए है हथियारों के लिए नहीं

(b) इस समझौते से अमेरिका ने अपने घरेलू परमाणु अधिनियम की धारा 123 में परिवर्तन किया

[पहले इसके तहत माना जाता था कि NPT पर गैर-हस्ताक्षर कर्ता देशों को परमाणु ईंधन नहीं देगा]

(c) भारत में परमाणु अनुसंधान केन्द्रों को सिविल (14 व सैन्य परमाणु केन्द्रों में बाटा गया है। IAEA सिविल परमाणु अनुसंधान केन्द्र का निरीक्षण करेगा समझौते के तहत यह विभाजन भारत स्वयं करेगा।

समझौता लागू –

→ NSG ने भारत के लिए विशेष छूट प्रदान की [NPT पर हस्ताक्षर के बिना परमाणु ईंधन व तकनीक देगा]

→ IAEA के साथ भारत का विशेष समझौता इसके तहत सभी परमाणु केन्द्रों का निरीक्षण नहीं बल्कि सिविल परमाणु-अनुसंधान केन्द्रों का निरीक्षण

→ भारत का अन्य देशों के साथ सिविल परमाणु समझौता हुआ।

लाभ –

→ इससे भारत को उत्तरदायी राज्य का दर्जा मिला
→ भारत के परमाणु क्षेत्र का अलगाव समाप्त हुआ
→ भारत अमेरिका के मध्य सामरिक समझौते का प्रमाण है।
→ भारत को ऊर्जा उत्पादन के लिए रियक्टर व ईंधन मिलने का रास्ता साफ हुआ

आलोचना –

इससे भारत की न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास प्रभावित होगा। अमेरिका परोक्ष रूप में भारत को परमाणु अप्रसार के दायरे में लाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने इससे ईराक मामले में समर्थन की अपेक्षा की।

NSG की सदस्यता –

→ अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा NSG में भारत की सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। भारत परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यधिक विकसित राज्य है जो किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है व किसी भी संधि में सम्मिलित नहीं है इसलिए भारत के सम्मिलित होने से परमाणु अप्रसार प्रभावित होगा।

→ वर्तमान समय में NSG के द्वारा भारत को परमाणु रियक्टर और ईंधन दिया जा रहा है। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत को NSG की सदस्यता से क्या लाभ होगा। क्योंकि उसे पहले से ही ईंधन व रियक्टर मिल रहे हैं।

लाभ –

→ भारत का परमाणु निर्यात व्यवस्था से अलगाव समाप्त हो जायेगा

→ भविष्य में NSG के प्रावधान में होने वाले किसी भी परिवर्तन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

→ भारत को एक उत्तरदायी राज्य का दर्जा मिलेगा।

बाधा —

→ NSG की सदस्यता के लिए NPT पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है भारत के NSG की सदस्यता दिलाने का सबसे बेहतर उपाय है कि NPT के प्रावधान में परिवर्तन कर दिया जाये व भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दे दिया जाये।

* भारत इजराइल क्या एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए

→ प्राकृतिक मित्र है क्योंकि

→ रक्षा संबंध

→ आतंकवाद

→ तकनीकी

→ कृषि

लेकिन इजराइल, ईरान को आतंकवाद का प्रायोजन करने वाला राष्ट्र मानता है जबकि भारत नहीं मानता।

भारत फिलीस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक है

भारत इजराइल के मध्य अत्यधिक मधुर राजनीतिक आर्थिक व सुरक्षा के संबंध है किंतु कुछ मुद्दों पर गहरे मतभेद है।

फिलीस्तीन की वर्तमान समस्या व समाधान

इजराइल के अनुसार भविष्य के फिलीस्तीनी राज्य का निर्माण 1967 के भूभाग के आधार पर नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी है। (भारत 1967 के अनुसार करने का समर्थक)

→ इजराइल अभी भी पश्चिमी किनारे से अपनी बस्तियां हटाने को तैयार नहीं है और लगभग 50000 इजरायली बस्तियां अभी भी पश्चिमी किनारे में बनी हुयी है।

→ इजराइल के अनुसार भविष्य का फिलीस्तीनी राज्य गैर सैनिक राज्य होना चाहिए

→ हमास और फिलीस्तीनी सत्ता के बीच मतभेद भी समस्या के समाधान में बड़ी बाधा है।

→ हमास का मानना है फिलीस्तीनी समस्या का समाधान इजराइल का विनाश है जबकि फिलीस्तीनी सरकार के अनुसार (पश्चिमी किनारे) इजराइल से बातचीत होनी चाहिए

समाधान –

→ 1967 के भूभाग के आधार पर फिलीस्तीनी राज्य का निर्माण और फिलीस्तीन के शरणार्थियों को फिलीस्तीन वापसी का अधिकार

फिलीस्तीन का निर्माण पश्चिमी किनारे व गाजा से मिलकर होगा उसकी राजधानी पूर्वी येरुसलम होगी

→ पश्चिमी किनारे व गाजा क्षेत्र के बीच आवागमन का मार्ग प्रदान करना

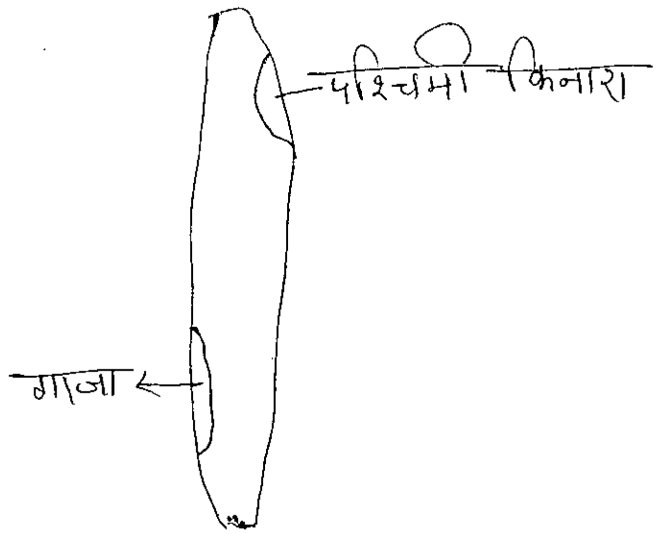

समस्या का सबसे तार्किक व व्यावहारिक समाधान द्विराष्ट्र है। द्विराष्ट्रवाद का तात्पर्य है कि फिलीस्तीन व इजराइल दोनों साथ साथ बने रहेंगे।

पश्चिम एशिया में भारत के हित

२००५ - पश्चिम की ओर देखो नीति

extended neighbourhood / विस्तारित पड़ोसी

→ तेल गैस — भारत के कुल तेल आयात का २०%
सऊदी अरब से

कतर (LNG)

भारत देश परिवर्तन कर सकता है लेकिन स्रोत परिवर्तित

→ पश्चिम एशिया से भारतीय मूल के लोग सर्वाधिक डालर भेज रहे है। इंडियन डायस्पोरा की नीति अमेरिका कनाडा के लोगों को ध्यान में रखकर बन गयी लेकिन UAE, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत

→ व्यापार व आर्थिक संबंध भी तेजी से बढ़ रहा है यह भारत और युरोपीय युनियन के व्यापार के बराबर होने वाला है। खाड़ी सहयोग परिषद से व्यापार के लिए अलग से बातचीत
खाड़ी सहयोग परिषद में कतर, सऊदी अरब, बहरीन UAE कुवैत ओमान

सऊदी अरब

→ भारत सऊदी अरब के बीच प्रत्यर्पण का समझौता हो चुका

→ 2012 में (ए के एंटनी) किसी पहली बार भारत के रक्षा मंत्री ने यात्रा की।

→ सामरिक सहभागिता की ओर अग्रसर – सऊदी अरब ने घोषणा की।

→ 2006 में 50 वर्ष में पहली बार वहां के राजा ने भारत की यात्रा की

→ सऊदी अरब हमारा पारंपरिक मित्र नहीं रहा है।

→ सऊदी अरब से दोस्ती द्वारा पाकिस्तान की इस्लामी एकता की दृष्टि को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है।

→ भारत, सऊदी अरब के लिए बड़ा बाजार

→ सऊदी अरब के साथ आतंकवाद पर सहयोग

→ महाराष्ट्र के संगठित अपराध को रोकना

पश्चिम एशिया से भारत के धार्मिक सांस्कृतिक संबंध है।
मुस्लिमों के कारन
ईरान के बाद विश्व में सर्वाधिक शिया भारत में

ईरान

→ तेल और गैस के क्षेत्र में

→ वर्तमान समय में भारत ने पुनः ईरान से तेल आयात बढ़ाने का निर्णय किया है क्योंकि ईरान भारत के लिए रुपये में तेल का निर्यात कर रहा है।

→ भारत और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने का भी प्रस्ताव किया गया था। परंतु निम्नलिखित कारणों से इस मुद्दे पर प्रगति नहीं हो पा रही है।

→ गैस की कीमत मूल्य पर मतभेद बने हुये है।

→ भारत का मानना है कि वह बाड़मेर में प्राप्त होने वाली गैस की कीमत चुकता करेगा

→ परंतु ईरान का तर्क है कि उसे ईरान में छोड़ी गयी गैस की कीमत चाहिए

→ पाइपलाइन की सुरक्षा के संबंध में भी मतभेद बने हुये है।

→ वर्तमान समय में इस गैसपाइपलाइन में चीन की दिलचस्पी बढ़ रही है। और पाकिस्तान से होकर

गैस पाइपलाइन चीन तक बिछाने की योजना है।

भारत के लिए ईरान का महत्व —

→ ईरान का भारत के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व है क्योंकि अफगानिस्तान जाने के लिए भारत के द्वारा ईरान के चाहबहार पत्तन का प्रयोग किया जाता है

→ मध्य एशिया में प्रवेश के लिए ईरान के बंदर अब्बास पत्तन का प्रयोग किया जाता है

→ अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी भारत व ईरान के दृष्टिकोण साझे है।

→ ईरान से रूस तक उत्तरी दक्षिणी कोरिडोर के भी निर्माण का प्रस्ताव है

भारत ईरान संबंधों पर अमेरिका का प्रभाव —

→ भारत ईरान के बीच के व्यापारिक व ऊर्जा संबंधों पर अमेरिका के द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध का सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

→ अमेरिका के द्वारा विश्व की सभी बैंकिंग संस्थाओं पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये है। इसलिए व्यापारिक लेनदेन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

→ आलोचकों के अनुसार इन प्रतिबन्धों से भारत को घाटा हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के लिए गेहूं का

निर्यात किया जबकि भारत जैसे देशों पर निर्यात के लिए प्रतिबन्ध लगाया

→ वर्तमान समय में भारत व ईरान के बीच वस्तुओं का व्यापार हो रहा है।

→ भारत ने ईरान से तेल आयात का भी निर्णय किया है। क्योंकि ईरान भारतीय रुपये में तेल देने को तैयार है इससे भारत को दोहरा फायदा होगा एक तो डालर खर्च नहीं करना होगा व रुपये की कीमत में सुधार होगा।

भारत ईरान के संबंध दोनों के राष्ट्रीय हितों पर आधारित है यद्यपि भारत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों को भी अनदेखी नहीं कर सकता।

मिश्र की वर्तमान समस्या

- 1920 में
  - कमालपाशा ने पंथनिरपेक्ष समाजवाद की नींव रखी
- 1924
  - ब्रदरहुड आन्दोलन (हसन अलबाना)
  - इस्लामी आधार पर शासन प्रणाली का संचालन
  - शरियत व कुरान के आधार पर
- इराक, सीरिया, लीबिया
  - में पंथनिरपेक्ष समाजवाद था
  - यद्यपि निरंकुश शासक
- सऊदी अरब, ईरान, बहरीन, जार्डन, यमन
  - धर्म का शासन

मिस्र –

- freedam and Justice Party (ब्रदरहुड की राजनीतिक इकाई)
  - इस्लामी आधार पर शासन
- Celebration Party (पंथनिरपेक्ष)

भारत – मिस्र

→ मिस्र के राष्ट्रपति मुर्सी ने मार्च 2013 में भारत की यात्रा की। मिस्र और भारत के बीच निम्नलिखित गैर सामरिक मुद्दों पर सहयोग का निर्णय किया गया

→ सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम

→ उच्च शिक्षा में सहयोग

→ कृषि क्षेत्र में सहयोग

→ स्वास्थ्य और अंतरिक्ष दूरसंवेदन के क्षेत्र में सहयोग

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति के समझौते पर हस्ताक्षर हुये

→ साइबर सुरक्षा

→ विश्वविद्यालयी क्षेत्र में सहयोग

→ बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग

→ सूचना तकनीकि क्षेत्र में सहयोग

~~→ अरब स्प्रिंग उ~~

अरब स्प्रिंग का अपूर्ण ~~अन्त~~ लक्ष्य

→ अरब स्प्रिंग को पश्चिम एशिया में अरब अवेकनिंग के नाम से संबोधित किया गया। परन्तु मिस्र में सैनिक सरकार का नियंत्रण हो गया

→ सीरिया में अभी भी संघर्ष जारी है

→ लीबिया जैसे देश में विजातीय संघर्ष बना हुआ है

→ सऊदी अरेबिया, UAE अभी भी लोकतांत्रिक आन्दोलन के दायरे से बाहर हैं

सीरिया संकट

वर्तमान में गृह युद्ध जारी है इसमें 40-50 ~~लाख~~ हजार लोग मारे गये हैं और अभी रासायनिक हथियार का भी प्रयोग किया गया है। लाखों शरणार्थी पड़ोसी राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं।

सीरिया का तर्क –

→ सीरिया का दावा है कि पश्चिमी देश ईरान को अलग थलग करने के लिए सीरिया के शासन को हटाना चाहते हैं।

→ अमेरिका, सऊदी अरब इज़राइल व तुर्की को मदद देकर सीरिया की सरकार को उखाड़ फेकना चाहता है ~~क्योंकि~~

→ सीरिया द्वारा फिलीस्तीन का समर्थन

पाश्चिमी देश

→ सीरिया के द्वारा लोकतंत्र की हत्या

→ मानवाधिकार का हनन

→ पश्चिमी देश सैन्य हमले के समर्थक लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने सैन्य हमले का समर्थन नहीं किया है।

→ चीन व रूस किसी भी सैनिक हमले के विरोधी हैं।

→ अमेरिका व रूस के बीच सहमति बन गयी है कि मामले का शान्तिपूर्ण समाधान होगा।

→ सुरक्षा परिषद ने रासायनिक हथियार को समाप्त करने के लिए टीम भेजी है।

→ सीरिया सरकार के विरोधी लड़ाकुओ मे फूट पड़ गयी है

यूरोपियन यूनियन

1951 में यूरोपीय स्टील एवं कोयला यूनियन के रूप में की गई

1956 में इसका नाम बदलकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय

1967 - यूरोपीय समुदाय

1992 - मास्ट्रिच संधि के बाद नाम यूरोपीय यूनियन

वर्तमान में 28 सदस्य

2009 में लिस्बन सन्धि के द्वारा पुनः बदलने की कोशिश

संरचना

यूरोपीय संसद -

सदस्यों का प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें देश की जनसंख्या के अनुसार उस देश का संसद में प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाता है।

इसके द्वारा EU के लिए विधायन, बजट निर्माण

यूरोपीय परिषद - agenda तय करती है

- इसमें प्रत्येक देश के शासनाध्यक्ष / राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

यूरोपीय मंत्रिपरिषद - निर्णय लेते हैं

इसमें विषय विशेष से संबंधित प्रत्येक देश के मंत्री भागीदार होते हैं।

E.U. → यूरोपीय न्यायालय

- मंत्रि परिषद
  - प्रत्येक देश के मंत्री
- यूरोपीय आयोग
  - → यूरोपीय परिनियम द्वारा लिए गये निर्णयों को लागू करना है।
- यूरोपीय संसद
  - ⇓ प्रत्यक्ष निर्वाचन
  - ⇓ देश की जनसंख्या के अनुसार
- यूरोपीय परिषद
  - ⇓ प्रत्येक देश (28) के शासन अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है

यूरोपीय आयोग –

ये EU की कार्यकारी प्रशासनिक इकाई है। इसका मुख्य कार्य EU द्वारा लिए गये निर्णयों को लागू करना है।

यूरोपीय न्यायालय –

देश के मध्य विवाद, व पारराष्ट्रीय अपराधों के मामले में कार्य करता है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक –

यूरो जोन के लिए एक समान मौद्रिक नीतियों का निर्माण करना

यूरोपीय देशों को यहां की साझी ईसाई सभ्यता आपस में बेहतरीन ढंग से जोड़ती है।

सिंगल यूरोपियन एक्ट / यूरोपीय एकीकरण अधिनियम 1985 –

इसके द्वारा यूरोपीय समुदाय ने मौद्रिक एकीकरण का निर्णय लिया इसको क्रियान्वित करने के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना हुयी

इसके द्वारा 1999 में यूरोपीय यूनियन के 17 देश में यूरो नामक साझी मुद्रा का प्रयोग किया गया।

कोपेनहेगन मानदण्ड –

इसके अंतर्गत यूरोपीय यूनियन में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए न्यूनतम मानदण्ड का निर्धारण किया गया (1993) ये मानदण्ड है –

→ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली
→ मानव अधिकारों का बेहतर रिकार्ड
→ उदारीकृत आर्थिक प्रणाली

शेनजेन सन्धि –

इसे 1995 में लागू किया गया इसमे यूरोपीय यूनियन के 22 राज्य और चार राज्य यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है लेकिन शेनजेन संधि व क्षेत्र के भाग हैं चार गैर सदस्यों में आइसलैण्ड, नार्वे, लिचिन्टीन, और स्विटजरलैण्ड है। यूरोपीय यूनियन के वे सदस्य जो शेनजेन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं उनमें बेल्जियम साइप्रस, रोमानिया, तथा इंग्लैण्ड हैं आयरलैण्ड ने स्वयं को इस संधि से पृथक रखा है

→ इस सन्धि के अनुसार ~~इस क्षेत्र के~~ सदस्य देशों के सभी नागरिक समूचे क्षेत्र में मुक्त आवागमन कर सकते हैं इसके लिए पासपोर्ट व वीजा की आवश्यकता नहीं है।

ट्रांजिट वीजा – बिना रुके निकल जाने के लिए

यूरोजोन —

→ 1999 में यूरोपीय (17) देशों ने मिलकर साझा मुद्रा के प्रयोग का निर्णय लिया इसको क्रियान्वित करने के लिए 1998 में एम्स्टर्डम सन्धि हुयी जिसके अनुसार यूरोपीय केन्द्रीय बैंक स्थापित हुआ। वे राज्य जो यूरोजोन के भाग नहीं हैं उनमें बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैण्ड, रोमानिया, स्वीडन और इंग्लैण्ड

यूरोपीय जोन में सम्मिलित राज्यों में आस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन जैसे यूरो जोन के राज्य वर्तमान समय आर्थिक मंदी के शिकार हैं। इसके प्रभाव पूरे यूरोजोन पर पड़ रहा है

यूरोजोन में शामिल होने की शर्तें —

(a) सदस्य देश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए

(b) ब्याज दर कम होनी चाहिए

(c) विनिमय दर स्थायी होना चाहिए

(d) सरकार के ऊपर ऋण कम होना चाहिए

(e) मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए

यूरोजोन संकट उत्पन्न होने का कारण -

(a) यूरोजोन के सदस्यों ने उपयुक्त मानकों का पालन नहीं किया

(b) पुर्तगाल स्पेन ग्रीस जैसे देशों ने कल्याणकारी योजनाओं पर अत्यधिक पैसा खर्च किया जिससे सरकारें ऋण के बोझ से डूब गयीं

समाधान -

(a) यूरोपियन सेंट्रल बैंक में बेलआउट पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है

(b) इन समस्याओं को हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन द्वारा दो प्रकार के उपाय किये गये हैं।

→ यूरोपीय वित्तीय स्थायित्व सहायता

→ यूरोपीय वित्तीय स्थायित्व तंत्र

(c) इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भी इन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

(d) इस आर्थिक संकट से राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुये व जर्मनी के नागरिकों ने जर्मनी के द्वारा संकटग्रस्त देशों की आर्थिक सहायता पर आपत्ति व्यक्त की जर्मनवासियों ने कहा जर्मन करदाताओं का पैसा इस प्रकार खर्च नहीं होना चाहिए

का एक चार्टर तैयार किया गया है जो सभी राज्यों पर वैधानिक रूप में लागू होगा

2001 में नीस सन्धि के द्वारा 10 यूरोपीय देशों को ~~नीस~~ सन्धि यूरोपीय यूनियन में शामिल किया गया

यूरोपीय यूनियन का महत्व

→ यूरोपीय यूनियन को copy नहीं कर सकते लेकिन

Domino effect – एक घटना का प्रभाव दूसरे पर कैसे पड़ता है।

भारत फ्रांस के बीच रक्षा संबंध

भारतीय इतिहास में रक्षा संबंधों में सबसे बड़ा समझौता (mother of alls difference age) भारत फ्रांस के बीच हुआ। इसके अन्तर्गत भारत ने फ्रांस से 126 लड़ाकू विमानों की खरीद की

यह समझौता 12 बिलियन डालर का समझौता किया गया भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग केवल बेचने और खरीदने तक ही सीमित नहीं है। बल्कि फ्रांस के द्वारा भारत को तकनीक का हस्तान्तरण भी किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत राफेल विमानों का उत्पादन ~~भारत~~ व संयोजन भारत में ही होगा। इसके अतिरिक्त जमीन से वायु में मार करने वाला मैत्री प्रक्षेपास्त्र ~~के~~ भी संयुक्त विकास की परियोजना पर हस्ताक्षर हो चुका है। फ्रांस ने स्कार्पीन पनडुब्बी के निर्माण के लिए भारत को तकनीक हस्तान्तरण का समझौता किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत फ्रांसीसी रक्षा संबंध भारत रूसी रक्षा संबंधों के माडल पर विकसित हो रहे हैं

भारत फ्रांस के बीच सिविल परमाणु समझौता भी संपन्न हो चुका है यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस के कुल बिजली

उत्पादन का 78 % भाग परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होता है जबकि भारत के परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता वर्तमान समय में 4780 MW है। इसे बढ़ाकर 2032 तक 63000 MW करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

→ भारत और फ्रांस के बीच साझे लोकतांत्रिक मूल्य सहयोग को प्रभावी बनाते हैं। फ्रांस सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थक है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भी दोनों के बीच सहयोग हो रहा है। ~~~~ माली में फ्रांस के द्वारा संचालित कार्यवाही का भारत ने समर्थन किया —

→ भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 9 बिलियन डालर का है और भारत ने फ्रांस के एक उपग्रह का भी फरवरी 2013 में प्रक्षेपण किया जिसमें PSLV C-20/SARAL

भारत – जर्मनी

→ भारत जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी सहयोगी है वर्ष 2008 में भारत जर्मनी विज्ञान और तकनीक केन्द्र की स्थापना नयी दिल्ली में हुयी।

→ यह बिन्दु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भारत जर्मनी के बीच ऊर्जा, पर्यावरण, कोयला और जल तकनीक के विकास के लिए संयुक्त अनुसंधान हो रहा है और दोनों के बीच के संबंध क्रेता और विक्रेता से बढ़कर संयुक्त और साझे उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं।

→ वर्ष 2013 में भारत जर्मनी के बीच अन्तसरकारी, सलाहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया

→ भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18 बिलियन डालर का है। यूरोपीय देशों में, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार जर्मनी है।
- यद्यपि भारत जर्मनी का 6वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

→ भारत जर्मनी के आर्थिक, व तकनीकी संबंधों को सामरिक संबंधों में परिवर्तित कर दिया गया है।

दोनों के बीच सामरिक सहभागिता का समझौता हो चुका है भारत यूरोपीय महाद्वीप के बाहर का एक मात्र राज्य है इसके साथ जर्मनी का सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर है। जर्मनी ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया तथा भारत के परमाणु आपूर्तिकता समूह की सदस्यता का भी समर्थन किया।

दोनों देशों के बीच, लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2012 को जर्मनी में भारत दिवस के रूप में मनाया गया तथा 2011-13 के बीच में जर्मनी ने भारत में जर्मन वर्ष बनाया

सामरिक — लम्बे समय की सहभागिता

भारत यूरोपीय संघ के बीच संबंध

आर्थिक

→ द्विपक्षीय व्यापार = 91.3 — 207 मिलियन डालर 2015 तक का लक्ष्य

→ निवेश

→ तकनीकी सहयोग

वर्ष 2000 से भारत EU शिखर वार्ता की शुरुआत

वर्ष 2004 के बीच भारत EU के बीच सामरिक सहयोग का समझौता हुआ है।

→ भारत व EU के साझे लोकतांत्रिक मूल्य आपस में दोनों को जोड़ते हैं।

बाधा —

श्रम मानक, पर्यावरणीय मानक, सुरक्षा के मानक

भारत व जर्मनी की बाधाएँ प्रतिस्पर्धी नहीं पूरक हैं

भारत - लैटिन अमेरिका

भारत - EU के बीच मुक्त व्यापार

भारत, E

→ वर्तमान समय में भारत EU के बीच मुक्त व्यापार के समझौते पर वार्ता चल रही है। इससे भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ हो सकते हैं

(a) सूचना तकनीक विशेषज्ञ, इंजीनियर, लेखाकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को यूरोपीय बाजारों में प्रवेश का अवसर मिलेगा।

(b) यूरोपीय यूनियन को निम्नलिखित लाभ होगा

→ उसे भारत के बड़े बाजार प्राप्त होंगे - बैंकिंग रिटेल क्षेत्र में यूरोपीय कंपनियों को फायदा होगा।

(c) मुक्त व्यापार वार्ता 2007 से चल रही है परन्तु यह अभी तक पूर्ण नहीं हुयी है। और इसमें निम्नलिखित समस्याएं बनी हुयी है।

→ यूरोपीय यूनियन के द्वारा अपने कृषि क्षेत्र पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। यूरोपीय यूनियन के सस्ते उत्पाद भारतीय बाजारों में

भारतीय उत्पादों के लिए कड़ी चुनौती हो सकते है।

→ EU भारत के विरुद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है जबकि भारतीय उत्पादों के स्वच्छता श्रम व पर्यावरणीय मानकों के आधार पर प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

लैटिन अमेरिका

NAFTA — North America free Trade Area
USA, कनाडा, मैक्सिको से मिलकर बना है

1994 में तीनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार का समझौता किया। वस्तुओं में द्विपक्षीय

→ कृषि क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार का समझौता हुआ

→ द्विपक्षीय व्यापार
USA — कनाडा, कनाडा — मैक्सिको

→ पर्यावरण एवं श्रम मानक लागू करना।

NAFT की विशेषता —

→ एक तरफ विकसित देश हैं दूसरी तरफ विकासशील
→ विकसित और विकासशील — आर्थिक सहयोग
→ इससे पूरे लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का विकास है।

स्पेनिश भाषा बोली जाती है — लैटिन अमेरिकी देश

FTAA – Free Trade area of America

पैन अमेरिकाना | सर्व अमेरिकावाद

उत्तरी व दक्षिण अमेरिका में सहयोग

मर्कोसुर –

मर्कोसुर का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण अमेरिकी राज्यों का साझा बाजार | इसकी स्थापना 1991 में हुई

→ इसके संस्थापक राज्यों में अर्जेन्टीना, ब्राजील पेराग्वे, उरुग्वे थे, इनके बीच आर्थिक व राजनीतिक समझौता हुआ वर्ष 2012 में इसमें वेनेजुएला व बोलीविया को भी शामिल कर लिए गया |

→ उद्देश्य

→ मुक्त व्यापार को बढ़ावा

→ वस्तु मुद्रा और लाभों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और अंत में मर्कोसुर का विकास

(वा) प्रशुल्क संघ (कस्टम यूनियन) के रूप में हो चुका है

मर्कोसुर के साथ भारत का तरजीह व्यापार का समझौता है |

CELAC — लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई देशों का आर्थिक समुदाय संगठन

दिसंबर 2011 में 33 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों ने एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन की स्थापना की इसे आर्गेनाइजेशन आफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS का विकल्प माना जा रहा है। इसमें अमेरिका व कनाडा को शामिल नहीं किया गया है

उद्देश्य –

→ क्षेत्रीय व्यापार एवं एकीकरण को बढ़ावा देना

→ वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान सदस्य राज्यों की सहायता जिसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कोष गठित होगा –

संगठन में विद्यमान मतभेद

→ ब्राजील इस संगठन का सबसे संपन्न देश है जबकि हैती इस संगठन का सबसे गरीब देश है।

→ क्यूबा की विचारधारा साम्यवादी है जबकि वेनेजुएला की नीतियां लोकप्रिय हैं जिसका झुकाव समाजवाद की ओर [वेनेजुएला – तेल बिक्री से प्राप्त पैसे आम लोगों में बांटना, वितरण पर ज्यादा ध्यान उत्पादन पर नहीं, लेकिन देश पर अंततः संकट आयेगा, अर्थव्यवस्था में विविधता का अभाव)

बनाना प्रणाली — शासन प्रणाली न्यायिक, भ्रष्टाचारपूर्ण अर्थव्यवस्था कच्चे माल के निर्यात पर आधारित है

→ कोलंबिया – उदारवादी

→ इसके अतिरिक्त वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ बोलिविया अमेरिका विरोधी देश है। जबकि कोस्टारिका, अलसल्वाडोर, होंडुरास, पेरु इनका चिली का अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता है।

युनासुर –

का शाब्दिक अर्थ दक्षिण अमेरिकी राज्यों का संघ है। 12 राज्यों ने मिलकर 2008 में इसका निर्माण किया। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। क्षेत्र का समुचा विकास करना केवल आर्थिक एकीकरण ही नहीं

→ सैनिक खर्चों को घटाना

→ अपराध को घटाना

→ लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रोत्साहन

→ ऊर्जा व वित्तीय व्यवस्था का एकीकरण

समस्याएं –

→ वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच सीमा विवाद को हल करना

→ आधारभूत संरचनाओं और कनेक्टीविटी का विकास करना ब्राजील चिली कोलंबिया, अर्जेन्टीना व कोलंबिया [illegible] देशों के बीच संबंधों का संतुलन बनाए रखना

→ दक्षिण - दक्षिण संबंध
→ तीसरी दुनिया की एकता का विचार
→ गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का प्रभाव
→ संयुक्त राष्ट्र संघ, G-77
→ साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध

} लैटिन अमेरिका व अफ्रीका के साथ हमारी विदेश नीति

1990 के पूर्व संबंध लैटिन अमेरिका से वैचारिक थे जबकि अब आर्थिक व्यापारिक हो गये हैं

→ द्विपक्षीय व्यापार [आटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल, IT का निर्यात भारत द्वारा]

ब्राजील के साथ भारत के व्यापार मे 10 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि

→ ऊर्जा सुरक्षा
- → ब्राजील – ऐथेनाल
- → वेनेजुएला से तेल व गैस

→ राजनीतिक सहयोग — IBSA

भारत-ब्राजील

सामरिक सहयोग — G-20, BRICS, NSG में G-4

ब्राजील ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया

ब्राजील — बड़ा कृषि उत्पादक

[illegible] विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए

BASIC — Brazil S. Africa India china

भारत -- अफ्रीका

अफ्रीका के साथ भारत के संबंध नये नहीं बल्कि ऐतिहासिक नहीं है

→ फोकस अफ्रीका पालिसी -
व्यापार, वाणिज्य व अर्थ का महत्व

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश -
[अफ्रीका में ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषी है]

(1) पहले व्यापार निवेश द्विपक्षीय था

(2) उपक्षेत्रीय → SADC - Suthern African Development community.
→ ECOWAS - Economic Community of west African states
→

(3) 2008 से भारत अफ्रीका कानक्लेव
दूसरी बैठक इथियोपिया (आदिस अबाबा) में हुयी

(4) द्विपक्षीय व्यापार
→ भारत का सर्वाधिक फार्मास्युटिकल निर्यात नाइजीरिया को होता है।
→ 2015 तक दोनों के बीच के 70 बिलियन डालर तक बढ़ने का निर्धारण किया गया है।

(5) निवेश -- रिलायंस महिन्द्रा टाटा द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में निवेश

New growth pole - India

लगभग 28 भारत लोग – मॉरिशस युगांडा केन्या, S. Africa में रहते है।

→ लोक तांत्रिकता

→ ऊर्जा सुरक्षा – भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति का 20% भाग अफ्रीका से आ रहा है। सूडान नाइजीरिया अंगोला प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं
नाईजीरिया – रेल के बदले तेल

क्षमता निर्माण कार्यक्रम –
मानव संसाधन का विकास लोगों को शिक्षा, चिकित्सा देना व उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा देना
NEPAD – New Partnership for Africa's States इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुयी।

राज्य-राज्य व्यापार
केवल व्यापार

निजी कंपनियां भी शामिल
क्षमता निर्माण कार्यक्रम

Indian Technical and economic Cooperation के अन्तर्गत अफ्रीका महाद्वीप के 1000 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 15000 अफ्रीका छात्रों को प्रतिवर्ष भारत में शिक्षा दी जा रही है

→ 1991 के पूर्व अफ्रीका कोष संचालित किया जाता था
Axal for Resistance against Imperialism Polarinasim, Apanphiad (रंगभेद की नीति)

TEAM-9 Project -

शान्ति सेना कार्यक्रम -

भारतीय शान्ति सेनाओं की तैनाती अफ्रीका महाद्वीप में सदैव रही है। वैश्विक आतंकवाद, नशीली दवाओं का व्यापार एवं नियन्त्रण में सहयोग

दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यक्रम

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

→ सैन्य प्रशिक्षण

→ सिविल सेवा प्रशिक्षण, सूचना तकनीक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, अस्पताल को e-networking से जोड़ दिया है। भारत के इंजीनियर डाक्टर वहां सेवा दे रहे हैं।

अफ्रीका महाद्वीप में भारत के लिए चुनौती –

→ भारत का अफ्रीकी महाद्वीप में केवल २५ देशों में दूतावास हैं जबकि चीन के ४८ देशों में दूतावास है।

→ भारतीय मीडिया की उपस्थिति भी अफ्रीका में नहीं है जबकि चीनी मीडिया ने अफ्रीका में अपनी बेहतर उपस्थिति बना ली है।

→ चीन और अफ्रीका के बीच का द्विपक्षीय व्यापार १०० बिलियन से ज्यादा का है जिसे २०१८ तक ३०० बिलियन डालर करने का लक्ष्य रखा गया है।

—

—

— —

सोमालिया समुद्री आतंक

→ जहाज पश्चिम के देशों के जबकि चलाने वाले भारतीय -

→ समुद्री सुरक्षा स्वयं में कठिन
अल्पविकसित देश

→ राजनीतिक अस्थिरता

→ जनजातीय स्वरूप

भारत - रूस

1990 के पूर्व भारत - USSR का संबंध वैचारिक था

→ भारत - रूस दोनों में कामन - भारत की आर्थिक प्रणाली सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता की प्रणाली थी।

→ रुपये व रूबल और कई बार बाटर (वस्तुओं का विनिमय) व्यापार

→ सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।

→ सोवियत संघ की मित्रता द्वारा चीन व पाकिस्तान को प्रतिसंतुलित किया जा सका।

→ 1971 से भारत अपने रक्षा हथियारों के आयात के लिए सोवियत संघ पर निर्भर था।

→ 1990 के पहले सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी था।

1990 के बाद रूस की विदेश नीति -

सोवियत संघ के विघटन से उपजा उत्तराधिकारी रूस सामान्य देशों का देश बन गया

→ पाश्चात्य पर निर्भरता की नीति

→ पुतिन ने रूस को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की नीति

रूसी विदेश नीति के 1990 के बाद के दो ट्रेंड

→ रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने रूस के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त की। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक दोयम दर्जे की शक्ति बन गया अब वह सुपरपावर नहीं रहा। परंतु रूस के आर्थिक उत्थान के बाद रूस का पश्चिमी देशों से अनेक मुद्दों पर मतभेद उभरे जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं –

⇒ अमेरिका व पश्चिमी देशों ने मानवाधिकार के मुद्दे पर रूस की आलोचना की चेचन्या संकट पर भी रूस की आलोचना की गयी

→ अनेक वैश्विक मुद्दों पर रूस की पूर्णतः उपेक्षा कर दी गई

→ नाटो का प्रसार रूसी भूभाग के निकट के क्षेत्र में होने लगा

ब्लादिमीर पुतिन की पालिसी

वर्ष 2000 में ब्लादिमीर पुतिन रूस के नये राष्ट्रपति बने उन्होंने पश्चिम पर निर्भरता की नीति के बजाए रूस को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न

किया। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने सामरिक संबंधों पर अत्यधिक बल दिया। तथा भारत के साथ परंपरागत मित्रतापूर्ण संबंधों को गतिशील बनाने का प्रयत्न किया। पुतिन ने अनेक मुद्दों पर अमेरिकी नीति का स्पष्ट विरोध किया।

[स्नोडेन को लेकर 1990 के बाद पहली बार अमेरिका-रूस के मध्य शिखर वार्ता रोक दी गयी]

मतभेद के बिन्दु -

→ रूस ने अमेरिका के द्वारा पूर्वी यूरोप में प्रक्षेपास्त्र की तैनाती का विरोध किया

→ ईरान और सीरिया के मुद्दे पर रूस ने अमेरिकी नीतियों का विरोध किया

→ रूस के द्वारा जार्जिया संकट के दौरान अमेरिकी दृष्टिकोण का भी विरोध किया गया -

→ रूसी राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर अमेरिकी आलोचना का भी रूस ने विरोध किया।

→ वर्तमान समय में रूस के द्वारा स्नोडेन को शरणार्थी का दर्जा देने के कारण रूस व अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाली शिखर वार्ता को रद्द कर दिया गया।

किसी देश के नागरिक को शरणार्थी का दर्जा वहां के शोषण, नृजातीय संकट आदि के आधार दिया जाता है। जबकि स्नोडेन को नहीं

मतभेद –

रूस और चीन के बीच लंबी सीमा मिलती है जिसपर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।
रूस के पूर्वी भागों में चीन के लोग घुसपैठ करते रहते हैं।
→ उभरता चीन भविष्य में रूस के लिए बड़ी चुनौती सिद्ध होगा।

चीन के नये राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने अपनी पहली विदेश यात्रा में रूस का चयन किया व रूस को सबसे बड़ा सामरिक मित्र का दर्जा भी दिया। दोनो के दृष्टिकोण लगभग सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मामलो पर एक समान है।

सीरिया संकट, ईरान समस्या तथा सुरक्षा परिषद मे आने वाले विभिन्न प्रस्तावों पर दोनो का दृष्टिकोण साझा है। इसलिए दोनो के बीच का समकालिक संबंध अत्यधिक मधुर और मित्रतापूर्ण है।

रूस और अमेरिका में सहयोग

अमेरिका विश्व का एक मात्र सुपर पावर है इसलिए और विश्व व्यवस्था बनाये रखने के लिए वह अनेक राज्यों की सहायता भी लेता है इसलिए रूस व अमेरिका के बीच तमाम मतभेदों के बावजूद दोनो के बीच निम्न लिखित मुद्दों पर साझे दृष्टिकोण है।

→ अफगानिस्तान में आतंकवाद को प्रतिबंधित करना

→ परमाणु हथियारों के प्रसार को प्रतिबंधित करना।

→ वर्तमान समय मे सीरिया मुद्दे के समाधान के लिए भी दोनो मे सहयोग देखा गया।

→ रूस नाटो के ~~लिए~~ शांति के लिए सहभागिता कार्यक्रम का सहयोगी भी है।

→ दोनों के मध्य व्यापार

→ रूस की पूरी अर्थव्यवस्था तेल व गैस के निर्यात पर निर्भर है।

भ्रष्टाचार, नृजातीय समस्या, उद्योगों का आधुनिक न होना, आधारभूत संरचना का अभाव

चेचन्या समस्या – चेचन मूल के मुस्लिम रूस से अलग होना चाहते हैं।

चेचन्या रशिया के तेल उत्पादक राज्यों के करीब होने के कारण आर्थिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण

जॉर्जिया की रूसी जनसंख्या वाले (ओसेतिया) क्षेत्र में जॉर्जिया द्वारा हमला करने पर रूस द्वारा जॉर्जिया पर आक्रमण कर दिया जिससे वह नाटो में शामिल हो गया।

अजरबेजान व आर्मेनिया में संघर्ष

भारत – रूस

विश्वसनीय सहयोगी

रक्षा सामग्री –

1990 के बाद भारत – रूस के संबंधों के आधार में परिवर्तन हुआ 1990 के पहले वैचारिक था उसके बाद आर्थिक व राष्ट्रीय हितों पर आधारित हुआ

रूस हमें विशेष तकनीकी युक्ति के हथियार देता है जो अन्य देश नहीं देते [Special Strategic Partnership]

गोर्शकोव समझौता।

↳ देरी + मूल्य (रूबल की मूल्य वृद्धि के कारण)

जो दर्शाता है कि दोनों के मध्य बंधुता में कमी आ रही है।

भारत दुनिया में सर्वाधिक बड़ा हथियार आयातक है जबकि रूस की अर्थव्यवस्था हथियार निर्यात पर निर्भर है।

गोर्शकोव

परमाणु पनडुब्बी

नाभिकीय क्षमता

सहयोग केवल हथियार खरीदना का ही नहीं बल्कि

दोनो के मध्य हथियारों का साझा उत्पादन होता है

→ ब्रह्मोस
→ सुखोई

[end user monitoring agreement]

अभी भी भारतीय सेना के 70% हथियार रूस के हैं।

भारत रूस से उतने हथियार खरीदता है जितने वहाँ की सेना भी नहीं खरीदती।

भारत ने रूस के nuclear liability bill मे ढील दी है

1990 के पहले भारत केवल रूस से हथियार आयात करता था, अमेरिका इजराइल फ्रांस से भी (cheap and best policy)

क्योंकि भारत की हथियार निर्माण पर निर्भरता कम नहीं होती दिखती अतः भारत रूस के संबंधों का भविष्य बेहतर है।

पुतिन की यात्रा - (2018)

→ भारत व रूस के बीच 2018 की शिखर वार्ता में निम्न लिखित द्विपक्षीय मुद्दों पर हस्ताक्षर हुआ

(A) भारत रूस संयुक्त फोर्स की स्थापना का निर्णय लिया गया जो 2 बिलियन डालर की राशि का होगा जिसके द्वारा प्रत्यक्ष निवेश आधारभूत संरचना तथा

हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया किया जायेगा

→ भारत में रूसी हेलीकाप्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना जिससे भारत में वायुयान उद्योग का विकास होगा।

→ दवाईयों, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र साफ्टवेयर के संबंध में साझा सहयोग

→ वैश्विक नौवहन उपग्रह व्यवस्था के उपयोग के पायलट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन जो अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग व्यवस्था का विकल्प होगा।

→ रूस के द्वारा भारत को 71 MI 17 हेलीकाप्टर तथा 42 सुखोई विमान प्रदान किये जायेंगे।

[रूस के समूचे ~~का~~ राजस्व का 30 % भारत को हथियार निर्यात से मिलता है]

→ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग — कुडनकुलम परियोजना

→ ऊर्जा सुरक्षा

ONGC ने अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश रूस के सखालिन क्षेत्र में किया है।

→ भारत के ~~[illegible]~~ मध्य एशिया के मध्य सामरिक संबंधों हेतु रूस का महत्व है — 4×4 — तापी प्रोजेक्ट

~~रूस~~

सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के पक्ष का समर्थन किया।

सुरक्षा परिषद में सदस्यता का समर्थक

शंघाई सहयोग परिषद में सदस्यता का समर्थक

सांस्कृतिक

→ दोनों देशों में सांस्कृतिक लेन देन

→ छात्रों का आदान प्रदान

व्यापार – रक्षा व्यय को निकालकर 10 बिलियन डालर से भी कम [सामरिक संबंधों की तुलना में कम)

कारण – रूस की अर्थव्यवस्था में विविधता का अभाव

→ रूसी व्यापारी पश्चिमी यूरोप से व्यापार करना पसंद करते हैं

→ निजी व्यापारी कठोर नियमों के कारण रशिया जाना कम पसंद करते हैं

→ भारतीय छात्रों का रुझान भी आस्ट्रेलिया की ओर

→ रूस में अति ठंड)

भारत व रूस के संबंधों का आकलन रूस-चीन के संबंधों के आधार पर नहीं भारत व रूस के द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर किया जाये (Non Zero sum game

India – ~~USA~~ – रूस चीन त्रिकोण

1996 में रूस की ओर से यह विचार आया

- → वैश्विक आतंकवाद
- → क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा
- → वैश्विक आर्थिक मंदी
- → सीरिया, ईरान पर
- → आर्थिक - व्यापारिक

~~किसके विरुद्ध~~ → USA

त्रिकोण का समर्थन

(1) रूस अपनी महाशक्ति का दर्जा बनाये रखने के लिए करता है

(2) रूस अमेरिकी शक्ति को प्रतिसंतुलित करना चाहता है।

चाइना - सहयोग - कारण

- → अमेरिका उभरते हुये चीन को प्रतिसंतुलित करने की नीति अपना रहा है।
- → तिब्बत के मामले में मानवाधिकार का आलोचक व ताइवान को हथियार देता है अमेरिका

भारत – त्रिकोण का समर्थक तो है लेकिन किसी देश विशेष के विरुद्ध नहीं क्योंकि भारत का संबंध अमेरिका से संतुलित है।

- → दुनिया बहुध्रुवीय बने इसलिए भारत द्वारा समर्थन

भारत चीन के मध्य द्विपक्षीय संदेह , व मतभेद समाप्त करके ही त्रिकोण सफल हो सकता है।

भारत – अमेरिका के बीच सामरिक वार्ता

भारत अमेरिका के बीच वर्ष २००९ से सामरिक वार्ता आरम्भ हुयी, जिसका चौथा चक्र इसी वर्ष २०१३ में नयी दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया

(a) → उच्च शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया

(b) भारत व अमेरिका ने २१वीं शताब्दी को ज्ञान पहल के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। इसके अंतर्गत Connect India कार्यक्रम की घोषणा हुयी जिसके द्वारा २०० अमेरिकी विद्यार्थी भारत में अध्ययन करेंगे।

(c) दोनों के बीच फुलब्राइट नेहरू सहभागिता भी आरंभ हुयी जिसके अन्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी और रमन फेलोशिप की भी शुरुआत हुयी।

(d) अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो तथा नासा के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त उपग्रह नौवहन व्यवस्था तथा वैज्ञानिकों के आदान प्रदान पर भी वार्ता हुयी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के अंतर्गत भारत में संक्रमित बीमारियों को समाप्त करने की

पहल की गयी। दोनो देशों ने जैव मेडिकल तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ाने पर बल दिया। AIDS समाप्त करने के लिए सहयोग का निर्णय लिया गया। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। दोनो देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन डालर है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 30 बिलियन डालर है

व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापार नीति फोरम की स्थापना हुयी तथा उड्डयन के क्षेत्र में भी सहयोग का निर्णय लिया गया।

सांस्कृतिक सहयोग के अन्तर्गत शिकागो विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानन्द पीठ स्थापित किया जारहा है तथा विज्ञान तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग का निर्णय लिया गया है।

→ दोनो के बीच सतत विकास ऊर्जा जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में भी बातचीत हुयी

→ दोनों के बीच अनेक क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। पूर्वी एशियाई सम्मेलन, आसियान रीजनल फोरम में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।

यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका हिमतक्षेस का पर्यवेक्षक राज्य है तथा 2014 के बाद अफगानिस्तान में भी भारत अमेरिकी सहयोग पर विचार किया गया।